पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

दीवानी याचिका अधिकारिता वाद संख्या -9312/2021

=====

राहुल कुमार, स्वर्गीय श्याम सुंदर तिवारी के पुत्र गाँव-नराना, थाना-बौन्सी, जिला-
बांका के निवासी।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, भवन निर्माण और आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. सचिव सह आयुक्त, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना।
4. सचिव-सह-आयुक्त, लोक निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
5. अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना।
6. अवर सचिव, भवन निर्माण और आवास विभाग, बिहार, पटना।
7. मुख्य अभियंता, भवन निर्माण और आवास विभाग, बिहार, पटना।
8. अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण और आवास विभाग, बिहार, पटना।
9. अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन मंडल, भागलपुर।
10. कार्यकारी अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रभाग, भागलपुर।
11. कार्यकारी अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रभाग, बांका।
12. अनुमंडलीय अधिकारी, भवन निर्माण विभाग, भवन उपखंड, बांका।
13. मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियांत्रिकी संगठन, बिहार, पटना।
14. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण अभियांत्रिकी संगठन, कार्य प्रभाग, मुंगेर।

15. आयुक्त, भागलपुर प्रभाग, भागलपुर।

16. कलेक्टर-सह-जिला मजिस्ट्रेट, बांका।

..... प्रतिवादीगण

=====

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति - प्रार्थी का आवेदन इस आधार पर आदेश दिनांक 14/01/2021 को अस्वीकृत किया गया है की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिनांक 16.12.2020 को दाखिल किया गया जो समय सीमा के पश्चात है अतः कालबाधित है ।

आवेदक के पिता 15.6.1979 को चौकीदार के रूप में योगदान दिये थे और 24/9/2003 को सेवाकाल में ही उनकी असमय मृत्यु हो गयी - आवेदक की मां ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन और अपने पति की मृत्यु उपदान और अन्य लाभों की मांग की थी - उसकी दावा दिनांक 28/04/2009 को अस्वीकार कर दी गई थी, जिसमें कहा गया कि आवेदक की मां के पति की नियुक्ति की वैधता को लेकर मुद्दा है - इस आदेश को आवेदक की मां ने सी .डब्लू .जे .सी संख्या 9681/2013 में चुनौती दी थी - जिस पर इस न्यायालय की एक समकक्ष ने अपने निर्णय दिनांक 29/8/2016 को दिया था - इस निर्णय के प्रावधानों के अनुसार उत्तरदाताओं ने मामला को विचार किया और दिनांक 29/11/2017 को आवेदक की मां के पति की सेवाएं नियमित स्थापना में 22.10.1984 के प्रभाव से स्वीकृत की गईं और उसे पेंशन भुगतान करने के लिए निर्देशित किया।

इसके बाद यह आवेदक ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन दिनांक 16-12-2020 को फाइल किया था जिसे दिनांक 14/01/2021 के आदेश द्वारा कालबाधित मानकर अस्वीकार कर दिया गया।

आवेदक का कथन है कि उसके पिता की नियुक्ति की वैधता स्वयं में एक विवादित मुद्दा घोषित की गयी थी - जिसे अंततः दिनांक 29/11/2017 के आदेश द्वारा निर्णीत

किया गया था - वित्त विभाग के संकल्प दिनांक 17/10/2013 के कंडिका 5(VI) के अनुसार जिसमें यह प्रस्तावित होता है कि सरकारी सेवाओं में किसी कर्मचारी को नियमित स्थापना में लाये जाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इसलिए आवेदक का आवेदन समय-सीमा के आधार पर गलत एवं नाजायज रूप से अस्वीकृत किया गया है।

राज्य उत्तरदाता ने यह विवाद किया कि आवेदक के पिताजी की मृत्यु 24/9/2003 को हो गई थी और आवेदक ने 5 वर्ष के समय के बाद आवेदन दिया था। बिहार सरकार के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प दिनांक 27/4/1995 के अनुसार समय सीमा के बाद दाखिल आवेदन खारिज करने योग्य ही होते हैं।

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए किसी भी आवेदन देने के लिए 5 वर्ष की समय सीमा सामान्य रूप से है - वर्तमान मामला एक सामान्य मामला नहीं है क्योंकि इस मामले में आवेदक के पिता की सेवाओं की वैधता का निर्णय केवल 29.11.2017 को ही हुआ था और आवेदक के पिता की सेवाएं 22/10/1984 से नियमित स्थापना में स्वीकृत की गई थी - इसलिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के दावे का मामला केवल दिनांक 29/11/2017 के निर्णय के प्राप्त होने के बाद ही उठ सकता था, जो वित्त विभाग के संकल्प दिनांक 17/10/2013 के कंडिका 5 (VI) के अनुसार भी कानूनी रूप से प्रावधान में है।

यह अभिनिर्धारित किया गया आवेदक का अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का दावा पांच वर्षों के अवधि तक जीवित रहेगा, 29.11.2017 से शुरू होकर, जिस दिन पर आवेदक के पिता की सेवाएं नियमित स्थापना में स्वीकृत की गयी थी, हालांकि 22/10/1984 से प्रभाव से। इस प्रकार, आवेदक द्वारा 16/12/2020 को फाइल किए गए आवेदन को कालबाधित नहीं माना जा सकता है।-

अतः प्रशङ्गत आदेश दिनांक 14.01.2021 जो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर बिल्डिंग सर्कल, भागलपुर द्वारा पारित किया गया है दोषपूर्ण एवं कानून के विपरीत होने के कारण

,निरस्त किया जाता है - -उत्तरदाताओं को निर्देशित किया जाता है की आवेदक के अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के आवेदन पर मेरिट के आधार पर फिर से विचार करे एवं इस आदेश प्राप्त/प्रस्तुतीकरण के चार सप्ताह के अंदर उचित आदेश पारित करें।

इस रिट याचिका को स्वीकृत किया गया।

=====

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

दीवानी याचिका अधिकारिता वाद संख्या -9312/2021

=====

राहुल कुमार, स्वर्गीय श्याम सुंदर तिवारी के पुत्र गाँव-नराना, थाना-बौन्सी, जिला-
बांका के निवासी।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, भवन निर्माण और आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. सचिव सह आयुक्त, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना।
4. सचिव-सह-आयुक्त, लोक निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
5. अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना।
6. अवर सचिव, भवन निर्माण और आवास विभाग, बिहार, पटना।
7. मुख्य अभियंता, भवन निर्माण और आवास विभाग, बिहार, पटना।
8. अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण और आवास विभाग, बिहार, पटना।
9. अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन मंडल, भागलपुर।
10. कार्यकारी अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रभाग, भागलपुर।
11. कार्यकारी अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रभाग, बांका।
12. अनुमंडलीय अधिकारी, भवन निर्माण विभाग, भवन उपखंड, बांका।
13. मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियांत्रिकी संगठन, बिहार, पटना।
14. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण अभियांत्रिकी संगठन, कार्य प्रभाग, मुंगेर।

15. आयुक्त, भागलपुर प्रभाग, भागलपुर।

16. कलेक्टर-सह-जिला मजिस्ट्रेट, बांका।

..... प्रतिवादीगण

उपस्थिति :

याचिकाकर्ताओं के लिए: श्री राजीव कुमार सिंह,

प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ता: श्री उदय शंकर सरन सिंह (जीपी-19)

श्री उदय भान सिंह, जीपी-19 के अ. लि.

=====

कोरम:माननीय श्री न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह मौखिक निर्णय

तारीख:28-02-2024

वर्तमान रिट याचिका दिनांक 14.01.2021 के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके द्वारा अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए याचिकाकर्ता के मामले को समय बाधित होने के कारण खारिज कर दिया गया है क्योंकि उसने केवल 16.12.2020 को विलम्ब से अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दायर किया था। याचिकाकर्ता ने याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने के लिए प्रतिवादी-प्राधिकरणों को निर्देश देने का भी अनुरोध किया है।

2. वर्तमान मामले का एक उतार-चढ़ाव वाला इतिहास है क्योंकि याचिकाकर्ता के पिता प्रतिवादी-विभाग में 15.06.1979 को चौकीदार के रूप में नियुक्त हुए थे और कहा जाता है कि उनकी अकाल मृत्यु 24.09.2003 को हुई थी। याचिकाकर्ता की मां ने तब अनुकंपा रोजगार देने के लिए आवेदन किया था और प्रत्यर्थियों से अपने पति के सेवानिवृत्ति बकाया और अन्य लाभों का भुगतान करने का भी अनुरोध किया था, हालांकि, जब वह प्रत्यर्थियों से कोई सांत्वना प्राप्त करने में विफल रही, तो उसने दीवानी याचिका क्षेत्राधिकार वाद संख्या 1106/2005 वाली एक रिट याचिका दायर की थी, जिसके बाद उसने विविध न्यायिकवाद संख्या 877/2009 वाली अवमानना याचिका भी दायर की थी, जिसमें उक्त रिट याचिका में पारित आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया गया था

जिसके बाद, सचिव, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना ने दिनांकित 28.04.2009 के आदेश के माध्यम से, याचिकाकर्ता की मां के पति की नियुक्ति की वैधता के बारे में कथित रूप से मुद्दा उठाते हुए याचिकाकर्ता की मां के दावे को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता की मां ने दीवानी याचिका अधिकारिता वाद संख्या-9681/2013 वाली एक रिट याचिका दायर करके इस अदालत के समक्ष दिनांकित 28.04.2009 के उक्त आदेश को चुनौती दी थी, जिसे इस अदालत की एक समकक्ष पीठ ने दिनांकित 29.08.2016 के फैसले के माध्यम से अनुमति दी थी। बिहार सरकार, पटना के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव को याचिकाकर्ता की शिकायतों पर गौर करने और याचिकाकर्ता की मां के पति के मामले को **सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमा देवी (3) और अन्य; (2006) 4 एस. सी. सी. 1** में प्रतिवेदित मामले में 53 वे पैराग्राफ में दिए गए निर्णय के संदर्भ में विचार करने का निर्देश दिया उत्तरदाताओं ने तब याचिकाकर्ता की मां के मामले पर विचार किया था और सरकार के उप सचिव, भवन निर्माण विभाग, द्वारा निर्गत दिनांकित 29.11.2017 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता के पति की सेवाओं को नियमित प्रतिष्ठान में 22.10.1984 के प्रभाव से नियमित किया गया था और यह निर्देश दिया गया था कि याचिकाकर्ता की मां को पेंशन का भुगतान किया जाए।

3. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने तब 16.12.2020 को अनुकंपा रोजगार प्रदान करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया, हालांकि, इसे अधीक्षक अभियंता, भवन मंडल, भागलपुर द्वारा पारित दिनांक 14.01.2021 के आक्षेपित आदेश द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि यह समय वर्जित है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने समर्पित किया है कि याचिकाकर्ता के पिता की नियुक्ति की वैधता स्वयं एक संदेह के तहत थी जिसे अंततः उपरोक्त आदेश दिनांक 29.11.2017 के माध्यम से स्पष्ट कर दी गई थी, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के पिता की सेवाओं को नियमित प्रतिष्ठान में नियमित किया गया था। इस प्रकार, वित्त विभाग के दिनांक 17.10.2013 के संकल्प के खंड-5 (vi) को ध्यान में रखते हुए, जो यह अभिनिर्धारित करता है कि किसी कर्मचारी को सरकार की नियमित सेवाओं में लाए जाने और उसकी मृत्यु के बाद, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का लाभ आश्रितों को दिया जाएगा। याचिकाकर्ता, मृतक कर्मचारी पर निर्भर होने के कारण, अनुकंपा रोजगार देने के लिए आवेदन दायर किया था, हालांकि, उसी समय की मनाही के आधार पर इसे अवैध

रूप से खारिज कर दिया गया है, इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि अधीक्षक अभियंता, भवन मंडल, भागलपुर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाए और प्रतिवादियों को अनुकंपा रोजगार के अनुदान के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।

5. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि चूंकि याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु 24.09.2003 को हुई थी, इसलिए आश्रितों का मामला, अनुकंपा रोजगार देने के लिए, पांच साल के अंतराल के बाद रोक दिया गया था और उसके बाद किया गया कोई भी आवेदन, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना के दिनांक 27.04.1995 के संकल्प के संदर्भ में खारिज होने योग्य है, इस प्रकार वर्तमान रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाना उचित है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख पर सामग्रियों का अवलोकन किया है। यह न्यायालय पाता है कि सामान्य तौर पर, मृतक की मृत्यु के पांच साल बाद उसके आश्रित द्वारा अनुकंपा रोजगार के लिए किया गया कोई भी आवेदन खारिज किया जा सकता है, हालांकि, वर्तमान मामला एक सामान्य मामला नहीं है क्योंकि तत्काल मामले में याचिकाकर्ता के पिता की सेवाओं की वैधता का फैसला सरकार के उप सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा पारित एक आदेश द्वारा 29.11.2017 को किया गया था, जिसके तहत और जिसके अंतर्गत, याचिकाकर्ता के पिता की सेवाओं को नियमित प्रतिष्ठान में 22.10.1984 को नियमित किया गया था। अतः अनुकंपा रोजगार प्रदान करने का कोई भी दावा केवल 29.11.2017 के अनुसार ही उत्पन्न हो सकता था, जो दिनांक 17.10.2013 के वित्त विभाग के संकल्प के खंड-5 (vi) के अनुसार भी कानूनी रूप से अनुमेय है। इसलिए, यह न्यायालय, उपरोक्त प्रावधानों की न्यायसंगत, कानूनी और रचनात्मक व्याख्या पर यह अभिनिर्धारित करना समीचीन समझता है कि अनुकंपा रोजगार देने के लिए याचिकाकर्ता का दावा 29.11.2017 से शुरू होकर पांच साल की अवधि के लिए जीवित रहेगा, जिस दिन याचिकाकर्ता के पिता को राज्य सरकार के नियमित प्रतिष्ठान में नियमित किया गया था, हालांकि 22.10.1984 से प्रभावी, इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता द्वारा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए दायर आवेदन 16.12.2020 पर, समय वर्जित है, इसलिए अधीक्षण अभियंता, भवन मंडल, भागलपुर द्वारा पारित 14.01.2021 का आदेश, विकृत और

कानून के विपरीत होने के कारण निरस्त किया जाता है और उसे याचिकाकर्ता के मामले पर अनुकंपा के आधार पर, गुण-दोष के आधार पर और ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में भी आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुति के चार सप्ताह की अवधि के अंदर नए सिरे से विचार करने और उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया है। इस

7. रिट याचिका की अनुमति है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

एस. एस. बी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।